



KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6

Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Mentorship — Polity MCQ - 39

ANSWER-KEY

- उत्तर (a)** पहली अनुसूची- राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंधा
दूसरी अनुसूची-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंधा
तीसरी अनुसूची- शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची- राज्य सभा में स्थानों का आवंटन
- उत्तर (c) कथन 1 सही है।** अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों पर नई पंचायती राज प्रणाली को अंगीकार करने की संवैधानिक बाध्यताएँ हैं।
कथन 2 सही है। पंचायतों के लिए सभी स्तरों पर पांच वर्ष का कार्यकाल नियत करना एक अनिवार्य प्रावधान है।
- उत्तर (d)** राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पांच वर्षों के बाद पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
पंचायत हेतु निर्वाचक नामावलियों के निर्माण और सभी चुनावों के अधीक्षण, दिशानिर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित होता है। उसकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
प्रत्येक राज्य, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित की गई योजनाओं के समेकन हेतु जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा।
- उत्तर (b)** वर्तमान में, सही सूमेलन है-
संघीय सूची - 100 प्रविष्टियाँ
राज्य सूची - 61 प्रविष्टियाँ
समवर्ती सूची - 52 प्रविष्टियाँ
- उत्तर (c)** 73वाँ संशोधन अधिनियम, पंचायती राज की आधारशिला के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। यह ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाहित ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय होती है। इस प्रकार यह पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से बनी एक ग्राम सभा होती है। यह राज्य की विधायिका द्वारा निर्धारित शक्तियों तथा कार्यों का प्रयोग तथा निष्पादन कर सकती है।
- उत्तर (b)** कथन 1 असत्य हैं। 44वें संशोधन अधिनियम में 'आंतरिक अशांति' नामक शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' नामक शब्द से प्रतिस्थापित किया गया।
कथन 2 सत्य है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे प्रस्तावों को पारित करने के लिए शसामान्य बहुमत के प्रावधान का संशोधन कर इसे 'विशिष्ट बहुमत' में परिवर्तित कर दिया गया। कथन 3 असत्य है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपातकाल की समाप्ति के लिए कार्यवाही आरम्भ करने के लिए लोक सभा को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए।
- उत्तर (c) कथन 1 सही है।** वर्ष 1934 में, भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रदूत एवं कट्टरपंथी लोकतंत्रवाद के समर्थक एम. एन. राय द्वारा भारत हेतु संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया गया था। 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने पहली बार भारत के संविधान का गठन करने हेतु आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की।
कथन 2 सही है। संविधान सभा का गठन नवम्बर, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई स्कीम के अंतर्गत किया गया था।
- उत्तर (a)** संविधान का समाजवादी झुकाव चिह्नित करने के लिए नए निदेशक तत्व जोड़ते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा चतुर्थ भाग में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
कथन 1 सही है। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और प्रस्तावना द्वारा प्रस्तावित समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त कदम उठाने हेतु राज्य को आदेशित करने के लिए अनुच्छेद 39। सम्मिलित किया गया है।
कथन 2 सही है। अनुच्छेद 48। द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन व वन्य जीवों की रक्षा के उपाय 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किए गए थे।
कथन 3 सही है। उद्योगों और अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देशित करने के लिए अनुच्छेद 43। सम्मिलित किया गया।
कथन 4 गलत है। अनुच्छेद 43B, (जिसमें सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन की बात है) 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था।
- उत्तर (c)** कथन 1 सही है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसलिए, नागरिकों के किसी वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए दिए गए राजनीतिक भाषण या किए गए वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण नहीं हैं।

10. उत्तर (b) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू की सूची सम्मिलित है। इस सूची में मूलतः केवल 14 भाषाएं थीं।

11. उत्तर (a) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

कथन 1 सही है। विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव श्रद्धा के समक्ष समता के अंतर्गत आता है।

कथन 2 गलत है। व्यवहार में समता, समान परिस्थितियों के लोगों के लिए है अन्यथा यह श्रद्धा के समक्ष समता का उल्लंघन होगा। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है। वर्ग विधान की अनुमति नहीं है परन्तु लोगों, उद्देश्यों आदि के यथोचित वर्गीकरण की अनुमति है। वर्गीकरण एकपक्षीय, कृत्रिम या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।

12. उत्तर (d) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के द्वारा भारतीय संसद, संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है।

किसी भी मूल अधिकार को कम करने या वापिस लेने के लिए संसद अधिकृत है। परन्तु यह उन मूल अधिकारों को न तो कम कर सकती है, न वापिस ले सकती है, जो संविधान के 'मूल ढांचे' का अंग हैं (केशवानंद भारती प्रकरण)।

कई अवसरों पर संसद ने विभिन्न अनुसूचियों में संशोधन किया है। मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां ही थीं और बाद में संशोधनों के माध्यम से 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया है।

13. उत्तर (c) कथन 1 सही है। पिछड़े वर्गों की पहचान, न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

कथन 2 सही है। अनुच्छेद 16 एक समर्थकारी प्रावधान है। यदि आवश्यकता हो तो यह राज्य को आरक्षण प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 (4) द्वारा अपेक्षित पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है, इसलिए इसमें SC, ST, और OBC समाविष्ट होते हैं।

14. उत्तर (d) विकल्प (a) सही नहीं है। इस प्रकार के बहुमत को साधारण बहुमत माना जाता है। इस बहुमत द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है।

विकल्प (b) सही नहीं है। इस प्रकार का बहुमत विशिष्ट बहुमत नहीं होता है एवं यह संविधान में संशोधन के प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं होता है।

विकल्प (c) सही नहीं है। संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के लिए, संसद के प्रत्येक सदन में, सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की नहीं बल्कि दो-तिहाई बहुमत के साथ, सदन की कुल सदस्यता के बहुमत की आवश्यकता होती है।

विकल्प (d) सही है। संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के लिए, संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है। इस प्रकार के बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं।

15. उत्तर (d) कथन 1 सही नहीं है। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती, जो संविधान के मूल ढांचे का गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमती को न तो रोक सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कथन 2 सही नहीं है। यदि संविधान संशोधन विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में परिवर्तन के लिए है, जो आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत (विशेष बहुमत नहीं) से इसकी पुष्टि अर्थात् सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से की जानी चाहिए।

16. उत्तर (c) विकल्प (c) अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वस्तुतः DPSP है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अन्य राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानजनक सम्बन्ध बनाये रखने हेतु प्रयास करेगा। अन्य मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है।

17. उत्तर (b) अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानसभा दोनों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अतः कथन 1 और 2 सही नहीं हैं।

अनुच्छेद 323A में अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न ही नहीं है जबकि अनुच्छेद 323B में अधिकरणों का पदानुक्रम बनाया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है।

18. उत्तर (B) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 40 को एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान किया है जो यह व्याख्या करता है कि "राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।" यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है।

19. उत्तर (c) संविधान निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति को संसद का सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि उसे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल के प्रावधानों के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो। एक सदस्य को दल-बदल कानून के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है-

यदि स्वेच्छा से उस राजनितिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट के पर वह सदन के लिए चुना गया है; यदि वह अपने राजनैतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी दिशा-निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है; यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और यदि कोई भी मनोनीत सदस्य छः माह के बाद किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के प्रश्न को राज्यसभा में सभापति द्वारा और लोकसभा में स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। 1992

में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस संबंध में सभापति/स्पीकर द्वारा दिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

20. **उत्तर (d)** कथन 1 गलत है क्योंकि, ऐसा विधेयक व्यपगत नहीं होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि, ऐसा विधेयक व्यपगत होता है।
21. **उत्तर (b)** 1993 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग भाग-IX' जोड़ा था। इसलिए, विकल्प 1 सही नहीं है।

इसका शीर्षक 'पंचायत' है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान सम्मिलित हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग IX को भारत के संविधान में जोड़ा (नगरपालिकाएं)।

पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में प्रावधान है। इसलिए, विकल्प 2 सही है।

प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समितियों के गठन के लिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

22. **उत्तर (b)** भारत में 'पंचायती राज' ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का प्रतीक है।

यह सभी राज्यों की विधायिकाओं के कानून द्वारा भारत के सभी राज्यों में स्थापित किया गया है ताकि लोकतंत्र को तृणमूल स्तर तक पहुँचाया जा सके। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया है।

23. **उत्तर (c)** 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य के लिए तीन प्रकार की नगर पालिकाओं को प्रावधान किया गया है। एक परिवर्ती क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत (जिसे कोई भी नाम दिया जा सकता है), परिवर्ती क्षेत्र से आशय उस ग्रामीण क्षेत्र से है जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।

एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद। एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। मंडल/ब्लाक पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच पंचायत का माध्यमिक स्तर है इसलिए, ब्लाक पंचायत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है।

24. **उत्तर (c) कथन 1 सही है।** अभी तक एक बार 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा

प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसमें प्रस्तावना में तीन नए शब्द 'समाजवादी', 'समन्वित' और 'संखंडता' तीन नए शब्द जोड़े गए थे।

कथन 2 सही नहीं है। संपत्ति अधिग्रहीत करने, बनाए रखने और बिक्री करने के अधिकार को (अर्थात् संपत्ति का अधिकार) 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-1 में शामिल कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि संपत्ति का अधिकार अभी भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन

मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें संविधान के भाग IV-A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।

25. **उत्तर (d)** अनुच्छेद 20 मनमाने और अतिरिक्त दंड के विरुद्ध आरोपी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है चाहे वह नागरिक, विदेशी या कानूनी निकाय जैसे कि कंपनी या निगम आदि कोई भी हो। इसलिए, सभी विकल्प सही हैं।

26. **उत्तर (d)** 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा निरपेक्ष नहीं है और इसके संवैधानिक एवं अन्य अपवाद भी हैं, जो नीचे वर्णित हैं :

कथन 1 सही है। भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के पास विशेष उन्मुक्तियां हैं (अनुच्छेद 361), जैसे वे अपने पद के अधिकारों और कर्तव्यों के उपयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं; पदावधि के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ या जारी नहीं रखी जाएगी।

कथन 3 सही है। संसद (या राज्य विधायिका) का कोई सदस्य किसी भी न्यायालय में संसद (या राज्य विधायिका) या उसकी किसी भी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा क्रमशः अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194)।

कथन 4 सही है। विदेशी संप्रभु (शासक), राजदूत और राजनयिक, आपराधिक और सिविल कार्यवाही से उन्मुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को राजनयिक उन्मुक्ति का अधिकार प्राप्त है।

27. **उत्तर (b)** सातवीं अनुसूची के अंतर्गत

शक्ति का पृथक्करण हमारे संविधान का संघीय प्रावधान है, जिसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सदन के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडलों के साधारण बहुमत से किए गए अनुमोदन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चूंकि संघ और राज्य सूची, दोनों ही सातवीं अनुसूची का भाग हैं। इसलिए केवल, कथन 2 सही है।

28. **उत्तर (c)** भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संसद और राज्य विधायिकाओं में लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा या विधानसभा उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में प्रदत्त उपबंध UPSC अध्यक्ष पर लागू नहीं होते हैं।

29. **(उत्तर (d))** अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा साधारण बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन के माध्यम से। परन्तु कुछ अन्य अनुच्छेद संविधान के कुछ प्रावधानों से साधारण बहुमत द्वारा अर्थात्, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान (सामान्य विधायी प्रक्रिया के समान) करने वाले सदस्यों के बहुमत से संशोधन का प्रावधान करते हैं।

इसलिए, संविधान में तीन प्रकार के संशोधन किया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन; संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन; संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधायिकाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन ।

30. उत्तर (a) अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसलिए कथन 1 सही है।

कथन 2 सही नहीं है। श्रद्धा के समक्ष समताश की अवधारणा ब्रिटेन से हुई है। इसका अर्थ है: (a) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार का अभाव (b) सभी व्यक्तियों पर न्यायालयों द्वारा देश का सामान्य कानून समान रूप से लागू होगा। सकारात्मक भेदभाव अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, न कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण अर्थात् अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

31. उत्तर (c) युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। इसके अनुसार, केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 में 8वीं अनुसूची में चार और भाषाओं को जोड़ा गया था - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ।

युग्म 3 सही सुमेलित है। संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी, जिसके अंतर्गत दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

32. उत्तर (c) संविधान में छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (चार पूर्वोत्तर राज्यों) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, लेकिन ये क्षेत्र संबंधित राज्य के अधिशासी प्राधिकार से बाहर नहीं है क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में अधिकांश शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। इसलिए, विकल्प (a) सही नहीं है।

राज्यपाल, स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन करने हेतु अधिकृत है। इस प्रकार, राज्यपाल उनका क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है या उनका नाम बदल सकता है या उनकी सीमाएँ परिभाषित कर सकता है। यदि स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल उस जिले को अनेक स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। इसलिए विकल्प (b) सही नहीं है।

प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यों से मिलकर बनने वाली जिला परिषद होती है जिसमें से चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक पदधारण करते हैं (जब तक कि परिषद समय पूर्व भंग न हो जाए) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। इसलिए, विकल्प (c) सही है।

जिला और क्षेत्रीय परिषदें भू-राजस्व निर्धारित और एकत्रित करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने के लिए अधिकृत है। गैर जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार देने और व्यापार करने पर जिला परिषद द्वारा नियंत्रण हेतु विनियमन बनाने की स्थिति में, ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए, विकल्प (d) सही नहीं है।

33. उत्तर (b) राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सभी प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के परामर्श से राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाता है। लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष के पास केवल दसवीं अनुसूची अर्थात् दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है।

34. उत्तर (d) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा एवं वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत से बाहर के तीर्थस्थलों से भिन्न तीर्थस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों के विरुद्ध सुरक्षा और पादप रोगों की रोकथाम सहित कृषि, राज्य सूची के अंतर्गत आता है।

35. उत्तर (d) कथन 1 सही नहीं है। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में कार्यपालिका अधिकार आमतौर पर राज्यों के ही पास रहते हैं परन्तु यह संविधान के या संघ को स्पष्ट रूप से इस प्रकार के कार्य को सौंपे जाने के किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होंगे।

कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 73 (1) (b) के अंतर्गत किसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध को लागू करने की कार्यपालक (अधिशासी) शक्ति पूर्णतया संघ की ही होगी, भले ही वह विषय संघ राज्य या समवर्ती सूची का हो।

36. उत्तर (d) बारहवीं अनुसूची - इसमें नगर पालिकाओं के दायरे में रखे गए निम्नलिखित 18 कार्यात्मक मदें सम्मिलित हैं :

नगर योजना सहित शहरी नियोजन;

भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन;

आर्थिक और मानसिक विकास के लिए

योजना बनाना; सड़क और पुल

घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति; सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; अग्निशमन सेवाएं;

शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन; विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों की हितों की रक्षा करना;

स्लम सुधार और उन्नयन;

शहरी गरीबी उन्मूलन;

पार्क, उद्यान, खेल मैदान जैसे शहरी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रबंधन; सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं का संवर्धन;

कब्र और कब्रिस्तान, अंतिम संस्कार और शमशान और विद्युत शवदाहगृह कांजी हाउस पशुओं के प्रति होने वाली

क्रूरता का निवारण: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े;

सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप, और सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक सुविधाएं तथा वधशालाओं और चर्मशोधन शाखाओं का विनियमन।

37. उत्तर (a) कथन 1 सही है। सदन का निर्दलीय सदस्य यदि ऐसे निर्वाचन के उपरान्त किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो वह सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य हो जाता है।

कथन 2 गलत है। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य यदि दल के निर्देशन के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो वह अयोग्य हो जाता है। लेकिन यदि सदस्य ने दल की पूर्ण अनुमति प्राप्त कर ली है और ऐसी कार्रवाई को दल द्वारा 15 दिनों के अंतर्गत उपेक्षा की गयी है तो वह सदस्य अयोग्य नहीं होगा।

कथन 3 गलत है। सदन का मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य सदन में अपना पद ग्रहण करने के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने के उपरान्त (न कि 6 महीने के अंदर) यदि किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह अयोग्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह अयोग्य नहीं होता है।

38. उत्तर (b) ग्राम सभा, ग्राम या गांव के स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर सम्मिलित गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय है। इस प्रकार, यह पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली ग्रामीण सभा है। यह गांव के स्तर पर राज्य की विधायिका द्वारा निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और विनिर्दिष्ट कार्यों का संपादन कर सकती है।

39. उत्तर (c) समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने श्योजना आयोग का गठन किया था।

40. उत्तर (a) 1993 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम: इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-LX जोड़ा है। इसे शंकायत शीर्षक दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 0 तक के प्रावधान सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक विषय सम्मिलित हैं। यह अनुच्छेद 243-G से संबंधित है। इसलिए, **कथन 1 सही है।**

यह अधिनियम देश में आधारभूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में मील का पत्थर है। यह प्रतिनिधी लोकतंत्र को सहभागी लोगतंत्र में परिवर्तित करता है। यह देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सृजन करने और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली क्रांतिकारी अवधारणा है। इसलिए, **कथन 2 सही है।**

यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। यह उन्हें संविधान के न्यायोचित क्षेत्र के तहत ले आया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नवीन पंचायती राज प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन हैं। फलस्वरूप, पंचायतों का गठन और या नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन, अब राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये समयबद्धता के लिए बाध्य हैं। इसलिए, **कथन 3 सही है।**

41. उत्तर (a) अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी कल्याण मंत्री का पद होना चाहिए। मूल रूप से यह प्रावधान बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा के लिए लागू था, किन्तु 94वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बिहार को हटा दिया और छत्तीसगढ़ और झारखण्ड को इसमें जोड़ा गया।

42. उत्तर (d) कथन 1 गलत है, क्योंकि छोटे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर के निकाय को गठित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर के पंचायत को गठित न करने का विकल्प प्राप्त है।

कथन 2 गलत है, क्योंकि पंचायती राज संरचना के तीनों स्तरों पर सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। **कथन 3 गलत है।** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर नहीं हैं। महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण केवल सामान्य वर्ग में ही नहीं होता है बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भी होता है।

43. उत्तर (d) कथन 1 गलत है, क्योंकि छोटे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर के निकाय को गठित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर के पंचायत को गठित न करने का विकल्प प्राप्त है।

कथन 2 गलत है, क्योंकि पंचायती राज संरचना के तीनों स्तरों पर सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। **कथन 3 गलत है।** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर नहीं हैं। महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण केवल सामान्य वर्ग में ही नहीं होता है बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भी होता है।

43. उत्तर (d) यह अधिनियम, नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र;
- मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषद विद्यमान है और
- पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला के लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है।

हालांकि, संसद स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों पर इस भाग के अनुबंधों का विस्तार कर सकती है। इसके लिए संसद ने शपंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया है।

44. उत्तर (c) अनुच्छेद 243C (5), पंचायत अध्यक्ष के विषय में प्रावधान निर्मित करता है कि
(a) ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्रावधानित पद्धति के अनुसार किया जाएगा, और
(b) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनके बीच में से किया जाएगा।
45. उत्तर (c) भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। 1967 ई० में सिन्धी को, 1992 ई० में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम (2003 ई) द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और सन्थाली भाषाओं को जोड़ा गया है।
46. उत्तर (b) भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उपबन्ध वर्णित हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में प्रावधान है।
47. उत्तर (d) वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा (उच्च सदन) के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। संघ एवं राज्यों में शक्तियों के वितरण का उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। संविधान में सूचित भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित उपबन्ध पंचम अनुसूची में वर्णित हैं।
48. उत्तर (a) प्रथम संविधान संशोधन 18 जून, 1951 को किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 174, 176, 314, 342, 372, और 376 में संशोधन किये गए तथा दो नए अनुच्छेद 31 शकश तथा शकश जोड़े गए। नौवीं अनुसूची में उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
49. उत्तर (a) सही सुमेलन इस प्रकार हैं-
संविधान के अनुच्छेद विषय
A. अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन
B. अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार

- C. अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
D. अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन

50. उत्तर (c) सही सुमेलन इस प्रकार है-
चौथी अनुसूची- इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है। छठी अनुसूची- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध वर्णित है।
आठवीं अनुसूची- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची- यह अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गयी। इसमें जोड़े गए भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक छानबीन की अधिकारिता से हटाया गया है।
51. उत्तर (c) अनुच्छेद 349- भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद 350-अपनी किसी शिकायत को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में प्रतिवेदन दे सकता है।
अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।
अनुच्छेद 351- हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश।
52. उत्तर (d)
विषय संविधान के अनुच्छेद
1. आकस्मिक प्रावधान 352
2. विधायी शक्तियों का वितरण 245
3. संघीय न्यायपालिका 124
4. नागरिकता 5
53. उत्तर (d) वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। 26 जनवरी, 1950 ई० को लागू संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
54. उत्तर (b) भारतीय संविधान में 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएँ जोड़ी गईं। मंत्रीपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए [अनुच्छेद 75 (1 क)]।
अतः उत्तर विकल्प (b) होगा।
55. उत्तर (a) 44वें संविधान अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद-31 में उल्लिखित सम्पत्ति के अधिकार का विलोपन कर उसे 300-1 में अन्तः स्थापित कर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। केन्द्र में इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे।
56. उत्तर (b) 2002 में 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इस संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 में एक नया उपखण्ड 21। जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल कर एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। स्पष्टतः यह संशोधन नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का एक उपक्रम है।

57. **उत्तर (b)** जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, के अनुसार भारतीय 1996 संविधान एवं भारतीय ध्वज का अपमान करने वालों को 6 वर्ष तक संसद तथा राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने से वंचित रखना, लोकसभा का चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि तथा उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव को प्रत्यादिष्ट न करने की व्यवस्था की गयी है।
58. **उत्तर (d)** संविधान के 73वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संविधान का चुनाव नियमित हो; महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त प्रदान किया जाए तथा 11वीं सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में पंचायतों को शक्ति का हस्तान्तरण अनिवार्य रूप से किया जाए।
59. **उत्तर (a)** जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, समवर्ती सूची में तथा लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
60. **उत्तर (d)** रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय विषय हैं।

